MR. CHAIRMAN: I have called Question No. 327. That is all.

Soviet President's Offer for Reduction of Nuclear Arms

*327. DR. RATNAKAR PANDEY: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention was drawn to the news-item regarding statement made by Soviet President in an address in France to European leaders; to reduce Soviet nuclear arms unilaterally; whether the West has agreed for immediate negotiations to take reciprocal steps in regard to such weapons;

(b) if so, whether Government consider it as a step forward in the realisation of a nuclear weapon free world as contemplated by the Prime Minister; and

(c) what steps have been taken by Government to evoke favourable response from the Western countries to the said Soviet proposal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. NATWAR SINGH): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Government has seen the USSR President's address to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, delivered at Strasbourg on the 6th July, 1989. The Soviet President stated, *inter-alia*, that it was time to begin talks within Europe on tactical nuclear systems between all the countries concerned and that if the NATO countries appeared ready to enter into negotiations on this subject, the USSR could make further unilateral cuts in its tactical nuclear missiles in Europe, without delay.

According to the Final Statement issued at the end of the last NATO Summit on the 30th May, 1989 negotiations on achieving "a partial reduction" of US and Soviet land-based, short-range nuclear forces "to equal and verifiable levels" can only begin once the implementation of an agreement on conventional force reductions in Europe is underway. The Statement also mentioned that no negotiated reductions in short-range nuclear forces, below the existing level on the side of NATO, would be carried out until the full implementation of the conventional force agreement.

The Soviet proposal for the elimination of all short-range nuclear weapons is, indeed, a step forward towards the objective of the complete elimination of all nuclear weapons, which constitutes the core of India's Action Plan on Disarmament unveiled by the Prime Minister at the Third Special Session of the General Assembly devoted to disarmament.

India is utilizing all available international fora and other opportunities for seeking the widest possible acceptance of its proposals under the Action Plan, which include the elimination of all short-range nuclear forces.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय सभापति जी, पूरी शताब्दियों के इतिहास में 19वीं शताब्दी का इतिहास सबसे अधिक रक्त रंजित कहा जायेगा, क्योंकि इस सदी में दो महायुद्ध हुए, जिनमें 58 लाख लोगों की जानें गयीं। मान्यवर, परमाणु हथियारों की होड़ यदि सम्पन्न राष्ट्रों में जारी रही तो एक ऐसा भयानक दिन भी इस धरती पर आ सकता है, जब सारी मानवता का नामोनिशान इस धरती से मिट जाये। भारत ने इस स्थिति को दुनिया में सबसे पहले पहचाना और भारत के प्रधान मंत्री माननीय श्री राजीव गांधी ने 9 जून, 1988 को यूनाइटेड नेशन्स जनरल असेम्बली के तीसरे विशेष अधिवेशन में परमाणु निरस्त्रीकरण पर जो प्रस्ताव रखा, उसकी सारी दुनिया में प्रशंसा की गई। मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय

मंत्री जी ने जो कुछ कहा है, उसके बाद 6 जुलाई, 1989 को सोवियत समाजवादी गणतन्त्र के राष्ट्रपति ने स्ट्रासबर्ग में यूरोपियन परिषद की संसदीय सभा में कहा कि सामरिक नाभिकीय पद्धतियों के संबंध में बातचीत होनी चाहिये और "नाटो" देश इस विषय पर बातचीत करने के लिये तैयार हों, तो सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ अविलम्ब अपने सामरिक नाभिकीय प्रक्षेपास्त्रों में एकतरफा कटौती कर सकता है। लेकिन "नाटो" ने साफ कहा कि कम दूरी वाले नाभिकीय हथियारों की संख्या वर्तमान स्तर से नीचे नहीं लायी जायेगी, जब तक कि पारस्परिक हथियार समझौते का पूरी तरह से क्रियान्वयन नहीं हो पाता। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नाभिकीय युद्ध को रोकने तथा नाभिकीय निरस्त्रीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये भारत ने कब तक, कहां-कहां पहल की है और मुख्य रूप से हथियारों को होड़ में लगे देशों में जनमत जागृत करने और उनकी सरकार को नीतियों पर दबाव डालने को क्या क्या कोशिश की है और उनका क्या नतीजा निकला है ?

श्री के. नटवर सिंह : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं, चूंकि प्रेजीडेंट गोर्बाचोव जो 6 जुलाई को अपना भाषण स्ट्रासबर्ग में दिया, उसका "नाटो" देशों से कोई खास जवाब नहीं आया और उसका कारण यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय हालात कुछ सुधरे हैं, बदले जरूर हैं, मगर बहुत से लोग जो इन हथियारों को बनाते हैं, चाहे न्यूक्लियर हों या नान न्यूक्लियर, उनकी विचारधारायें या दृष्टिकोण अभी बदले नहीं हैं और जो कोल्ड वार मेंटलिटी थी, जो यह भावना थी, वह भी बदली नहीं है। इसकी वजह से पूरी तरह से डिसआर्मामेंट का जो तनाव है, वह दूर नहीं हुआ है, परन्तु इसमें रद्दोबदल जरूर हुई है। जहां तक भारत का सवाल है, जैसा कि सभापति जी ने अभी सुना और माननीय मेम्बर ने कहा कि पिछले साल यूनाइटेड नेशन्स के स्पेशल सेशन में प्रधान मंत्री ने एक एक्शन प्लान रखा, जिसमें आज से लेकर 2010 तक अर्थात अगली शताब्दी तक प्रोग्राम हैं, अगर उसका पालन किया जायेगा तो ये सारे तनाव दूर हो नहीं होंगे मगर जो डिसआर्मामेंट हैं, वह भी सही मायने में हो सकता है। भारतवर्ष ने यूनाइटेड नेशन्स में, "नाम" में, कामन वैल्थ में आवाज उठाई है और आज से नहीं पिछले कई सालों से उठाई है और थोड़ा बहुत जरूर उसका असर पड़ा है, क्योंकि जो वातावरण बदला है... (व्यवधान)

डा० रत्नाकर पाण्डेय : कौन-कौन से देश हमारे सपोर्ट में हैं और कौन-कौन से विरोध में हैं ... (व्यवधान)...

श्री सभापति : उनको बोलने दें। वे जवाब देंगे ... (व्यवधान)

श्री के० नटवर सिंह : मैं बता रहा हूं। सिक्स नेशन इनीशियेटिव हैं। उसमें 6 देश हमारे साथ हैं और जो प्रधान मंत्री ने अपना एक्शन प्लान रखा, उसकी किसी ने मुखालफत तो नहीं की है। मैं ऐसे कैसे बताऊं कि कौन इसके खिलाफ है। सभी इसकी सहमति में हैं।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय सभापति जी, न्यूयार्क में निरस्त्रीकरण से संबंधित संयुक्त राष्ट्र महासभा के तीसरे विशेष अधिवेशन में नाभिकीय शास्त्र मुक्त, हिंसा मुक्त व्यवस्था की बात की गयी थी, मैं जानना चाहता हूं कि उसमें कौन कौन से देश हैं, जो इस कार्य योजना का, जिसका प्रस्ताव प्रधान मंत्री जी ने रखा था, समर्थन करते हैं और कौन कौन से देश ऐसे हैं, जिन्होंने इसका समर्थन नहीं किया और वे कौन से देश हैं, जिन्होंने इसका जवाब नहीं दिया ?

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.